हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है।
– अज्ञात

समाज और सिस्टम

कभी लड़की के चाल चरित्र को तो कभी उसके व्यवहार को दोष देने वाले बयान भी कम नहीं हुए। ऐसे में यह सवाल वाजिब है कि क्या हम और हमारी सरकार इन घटनाओं को महज एक तात्कालिक सनसनी के ही रूप में लेते रहने को अभिशप्त हैं ?

राधा जोशी

हैदराबाद रेप–मर्डर के चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद देशवासियों के एक बड़े हिस्से ने राहत की सांस लेनी शुरू ही की थी कि उन्नाव रेप पीड़िता की मौत ने दोबारा सबको मायूसी की चपेट में ले लिया। घटनाओं का यह क्रम बताता है कि हम नृशंस घटनाओं से उद्वेलित तो होते हैं लेकिन समाज और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस नहीं कर पाते।

2012 में दिल्ली की सड़कों पर निर्भया के साथ हुई हैवानियत ने देश में एक जागृति पैदा की। फिर पिछले साल ऐसी दूसरी लहर रुमीटू मूवमेंट के रूप में उभरी जब कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न मुद्दा बना। करीब पांच साल के अंतर पर आई इन हलचलों का समाज के मन–मस्तिष्क पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह इतना कारगर नहीं था कि ऐसी घटनाओं में थोड़ी भी कमी महसूस हो सके।

यौन हिंसा के मामलों को लेकर हमारे प्रशासनिक तंत्र की प्रतिक्रिया कमोबेश पहले जैसी ही रही। कुछ मामले ऐसे भी दिखे, जिनमें स्थानीय जनमत बलात्कारियों के पक्ष में जाता दिखा। कठुआ से लेकर उन्नाव और शाहजहांपुर तक ऐसे कई मामले हैं जहां ताकतवर आरोपी के सामने प्रशासनिक तंत्र पस्त नजर आया। कभी लड़की के चाल चरित्र को तो कभी उसके व्यवहार को दोष देने वाले बयान भी कम नहीं हुए। ऐसे में यह सवाल वाजिब है कि क्या हम और हमारी सरकार इन घटनाओं को महज एक तात्कालिक सनसनी के ही रूप में लेते रहने को अभिशप्त हैं ?

जब कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसके आरोपियों को फांसी देने की मांग करना और फिर सरकार की तरफ से कोई सुर्रा छोड़ दिए जाने पर खुशी से उछल जाना! इस हकीकत की तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है कि बलात्कार के मामलों में दोष साबित होने और सजा पड़ने का अनुपात जहां का तहां अटका पड़ा है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3.38 लाख मामले दर्ज हुए जिनमें 11.5 फीसदी मामले रेप के थे, लेकिन दोष हर चार मामलों में से सिर्फ एक में ही सिद्ध हो पाया।

समाज की सोच बदलने का काम लंबा समय लेता है, लेकिन कुछ ठोस उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करके हम देश की आबादी के मन में पैठा खौफ कुछ कम जरूर कर सकते हैं। जैसे, यह कि क्या रेप के मामलों में फैसला आने की कोई समय सीमा तय की जा सकती है? और यह कि ऐसे मामलों में सबूत जुटाने और उसे सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को फूल प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है? सरकार अगर संसद में हर साल एक निश्चित तिथि पर यौन हिंसा में सजा पड़ने का राज्यवार प्रतिशत बताए, तो भी पुलिस ढांचे का ध्यान इस पर बना रह सकता है।

चेतन स्वरूप

धर्म-दर्शन

रजनीश।

इन तीनों तम से परमात्मा अलौकिक और श्रेष्ट है। प्रकाश– स्वरूप ज्योतियों का ज्योति है, प्रकाशक और प्रकाशस्वरूप है। परमात्मा को ज्ञानस्वरूप बुद्धि से देखा जाता है परमात्मा को प्रकाशस्वरूप नेत्रों से देखा जाता है। परमात्मा के चेतन स्वरूप काआत्मा से ही अनुभव होता है। बोधस्वरूप – ज्ञानस्वरूप वही परमात्मा है। बोध स्वरूप यानि चेतनता ही उसका स्वरूप है। वह ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। इन्हेंजान लेने से परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। उस तत्वज्ञान के द्वारा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता हैद्य यथार्थ ज्ञान से परमात्मा में मिल जाता है। कर्म करने से पहले विचारों की गतिविधियों पर अवश्य ध्यान दें। जिससे कर्मों का फल सत – चित – आनंद स्वरूप हो।

संपादकीय

योजना का ऐलान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान कर सबको चौंका दिया। जल्द ही दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की सभी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। केजरीवाल का कहना है कि इस योजना पर आनेवाला प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। चूंकि राज्य सरकार का खजाना सरप्लस में है इसलिए उस पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्सिडी दी जा रही है, किराये में कोई फेरबदल नहीं की जा रही। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो महिलाएं टिकट खरीदने में सक्षम हैं, वे इस सब्सिडी को छोड़ दें ताकि जरूरतमंदों को मदद मिल सके। केजरीवाल का दावा है कि इस योजना से महिलाएं सुरक्षित यात्रा कर सकेंगी। अभी दिल्ली की बसों और मेट्रो के कुल यात्रियों में 33 फीसदी महिलाएं होती हैं। इस योजना के पीछे उनकी सुरक्षा का तर्क उतना दमदार नहीं है लेकिन महिलाओं को इतनी बड़ी सहूलियत देने की इच्छा वाकई मायने रखती है।

वैसे इस योजना के सामने आते ही कई तकनीकी प्रश्न भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मेट्रो में स्मार्ट कार्ड या टोकन के जरिए मुफ्त सफर का प्रावधान किया जाता है तो उसके लिए किराया वसूलने के तरीकों में परिवर्तन करने पड़ेंगे। ऐसे बदलावों के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर यह भी मुद्दा है कि दिल्ली सरकार मेट्रो को किस तरह भुगतान करेगी? भारी कर्जे पर खड़ी दिल्ली मेट्रो क्या भुगतान में किसी देरी या चूक को बर्दाश्त करने की हालत में है?

रिजर्व बैंक और आर्थिक विशेषज्ञ शुरू से ही कहते रहे हैं कि निवेश, कारोबार, रोजगार आदि के मामलों को मौद्रिक नीति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

समय बीतने के साथ

नवीन

भारतीय रिजर्व बैंक का लगातार तीसरी बार चौथाई फीसदी ब्याज दरें घटाना एक पैकेज के हिस्से की तरह आया है। अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना एनडीए सरकार–2 के अजेंडे में सबसे ऊपर है। पिछले दो–तीन वर्षों में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिऐ दो कैबिनेट समितियों का गठन किया गया, जिनके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होंगे। पहली समिति विकास दर और निवेश बढ़ाने पर काम करेगी, दूसरी रोजगार और कौशल विकास पर। इन उद्देश्यों के लिए कैबिनेट समितियों का गठन संभवतः पहली बार ही किया गया है। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के उत्तरार्ध में इकॉनमी सुस्त पड़ी और समय बीतने के साथ यह रुझान बढ़ता ही गया।

बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 5.8 फीसदी रही, जिसका असर पूरे वित्त वर्ष की विकास दर पर पड़ा है। 7.2 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले अंततः यह 6.8 प्रतिशत ही रही, जो पांच वर्षों में सबसे कम है। बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक है। चुनाव में मोदी सरकार को इसके लिए विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ी थी। मंत्रिमंडल गठन के दूसरे ही दिन श्रम मंत्रालय द्वारा जारी बेरोजगारी के

आंकड़ों के मुताबिक देश में 2017–18 में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत रही, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की जनवरी में लीक हुई रिपोर्ट में भी बताया गया था लेकिन तब नीति आयोग ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में ऋणात्मक 0.1 प्रतिशत हो गई, जबकि मैन्युफैक्चोरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर भी गिरकर 3.1 प्रतिशत पर आ गई।

जाहिर है, चुनौतियां काफी बड़ी हैं। प्रधानमंत्री की अगुआई में इन दोनों समितियों को प्रो–एक्टिव होकर कई सारे छोटे–बड़े फैसले करने होंगे। रिजर्व बैंक और आर्थिक विशेषज्ञ शुरू से ही कहते रहे हैं कि निवेश, कारोबार, रोजगार आदि के मामलों को मौद्रिक नीति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इन्हें बढ़ाने का जिम्मा सरकार को ही लेना होगा। रिजर्व बैंक ने विपरीत परिस्थितियों में लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती सरकार की तत्परता को देखकर ही की है।

यह फैसला उसने ऐसे समय में किया है जब बाजार में सस्ते कर्ज की मौजूदगी कुछ बड़ी समस्याओं की वजह भी बन सकती है। मसलन, मुद्रास्फीति को निर्धारित करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण कारक खाद्यान्न और ईंधन अभी जोखिम और अनिश्चितता के दायरे में हैं। मॉनसून कम से कम एक हफ्ते के विलंब से आ रहा है और ईरान से तेल आवक पूरी तरह रुक जाने पर भारत में तेल कीमतें क्या रंग पकड़ेंगी, यह स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार पकड़ाने के लिए ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है, जो तभी हो पाएगा जब बैंकों की ओर से सस्ते कर्ज का फायदा निवेशकों और ग्राहकों को मिले, पहले की तरह इसका फायदा वे खुद ही न उठाते रहें।

सूडोकु नवताल-5190

मध्यम

7	4	6		1		8		2
	5		8		7			
9				6				
	6		7	9		5		3
5				4				1
3		1		8	2		7	
				5				6
			4		3		9	
4		3		2		1	5	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5189 का हल

8	7	9	4	2	5	6	1	3
5	6	3	8	1	7	4	2	9
4	1	2	6	9	3	5	8	7
1	9	8	3	7	4	2	6	5
7	3	4	2	5	6	8	9	1
2	5	6	1	8	9	7	3	4
9	8	5	7	3	2	1	4	6
6	2	7	9	4	1	3	5	8
3	4	1	5	6	8	9	7	2

अपना ब्लॉग

एनकाउंटर से उपजे उत्साह की सीमाएं

योगिता यादव। 27–28 नवंबर की रात जिन चार दरिंदों ने हैदराबाद की 26 वर्षीया पशु चिकित्सक डॉ दिशा से दरिंदगी की, वे पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। खबरों के अनुसार पुलिस इन चारों आरोपियों मोहम्मद आरिफ, नवीन, शिवा और चेन्ना केशवुलु को उसी स्थान पर लेकर गई थी जहां अपराध को अंजाम दिया गया था। क्राइम सीन का रीक्रिएशन न्यायिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है, जिसमें आरोपियों को मौका–ए–वारदात पर ले जाकर पूरी घटना को विजुअलाइज करने की कोशिश की जाती है। इसी कोशिश के दौरान इन चारों का पुलिस एनकाउंटर हुआ।

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार की मानें तो मुख्य घटनास्थल, शम्साबाद के उसी फ्लाईओवर के नीचे जब पूरी घटना का रीकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, तब इन आरोपियों ने भागने की कोशिश की थी। यह तड़के 3 से 6 बजे के बीच की घटना है, जब रात का अंधेरा छंटने लगता है, धुंध छाने लगती है, पर सुबह की रोशनी दाखिल नहीं हुई होती। पुलिस भी यही कह रही है कि आरोपी धुंध का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने पुलिस पर पथराव करने की भी कोशिश की।